

## शहर के चरित्र को विकसित करने से ही बनेगी स्मार्ट सिटी

सिटीरिपोर्टर | भारत में स्मार्ट सिटी को लेकर नई-नई धारणाएं बुनी जा रही हैं। दूसरे देशों की चकाचौंध की नकल करने की बजाय हर शहर को उसकी विरासत और चरित्र को पहचान कर उसी आधार पर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना चाहिए। स्मार्ट सिटी का मतलब ही यही है कि उस शहर में घुसने पर उसकी पहचान की छाप दिखनी चाहिए। यह बात एनजी ग्लोबल एफजेड एलएएलसी के



सीईओ एवं दुबई के स्मार्ट सिटी कंसल्टेंट एन.जी. थॉमस ने गुरुवार को कही। वे एक होटल में चल रही स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिट एंड

एक्सपो के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। टैक्स वसूलो, सुविधाएं दो : आईजीबीसी की पॉलिसी एंड एडवोकेसी कमेटी के चेयरमैन वी.सुरेश ने कहा कि स्मार्ट सिटीज को स्मार्ट ग्रीन सिटीज में बदलने की जरूरत है। स्मार्ट सिटीज के लिए बांड्स, ग्रांट्स, टैक्स कलेक्शन आदि के जरिए वित्तीय संसाधन जुटाने में निजी और सरकारी क्षेत्र के मध्य उचित संतुलन आवश्यक है।

## ‘स्मार्ट सिटीज को स्मार्ट ग्रीन सिटीज में बदलने की जरूरत’

दो दिवसीय स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो का समापन

डेली न्यूज़, मिक्स रिपोर्टर

जयपुर। स्मार्ट सिटीज को स्मार्ट ग्रीन सिटीज में बदलने की जरूरत है। इससे पानी, बिजली की खपत कम होगी, कचरे का बेहतर निस्तारण होगा और लोगों को अच्छी आवास सुविधा मिल सकेगी। स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए, वित्तीय संसाधन आवश्यक है। स्मार्ट सिटीज के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने में निजी और सरकारी क्षेत्र के बीच संतुलन आवश्यक है। ये बात आईजीसी की पॉलिसी एंड एडवोकेसी कमेटी के चेयरमैन वी. सुरेश ने कही। ये शुक्रवार को होटल जयपुर मॉरियट में स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो 2018 के समापन सत्र में सम्बोधित कर रहे थे। इंडो-अमेरिकन चैंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से राजस्थान सरकार



एवं 'द ग्लोबल' के सहयोग से आयोजित समिट का समापन शुक्रवार को हुआ। वहीं एनजी ग्लोबल एफजेड एलएएलसी के सीईओ एवं दुबई के स्मार्ट सिटी कंसल्टेंट, एन जी. थॉमस ने कहा कि भारत को स्मार्ट सिटी अवधारणा में अन्य देशों की नकल नहीं होनी चाहिए। भारत को स्मार्ट सिटीज के विकास में योगदान देने वाली सबसे बड़ी एसेट इसमें रहने वाले लोग हैं। स्मार्ट सिटीज में पहले दिन से ही पैसा जेनरेट करना चाहिए। सेवाओं को उपलब्ध कराने के बदले छोटा सा शुल्क ले तो सकारात्मक वित्तीय परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

### फर्स्ट रेशन: सफलता की कुंजी है तकनीक, नवाचार और सहयोग

सेक्टर फॉर रिसर्च इन अर्बन अफेयर्स इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज की प्रो. कला सीतारामन श्रीधर ने कहा कि ई-कॉमर्स और इंटरनेट जैसे नए आर्थिक उद्योग बनना इस बात का संकेत है कि प्राचीन आर्थिक उद्योग विफल रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 'बक फ्रॉम होम' जैसी अवधारणाओं से ट्रैफिक और प्रदूषण कम होता है। भारत में बचत की दर 3.1 प्रतिशत

है, जबकि अमेरिका में यह सिर्फ 1.7 प्रतिशत है। यह इसलिए है कि भारत में आज भी लोग भ्रमण के लिए नकदी का इस्तेमाल करते हैं। नकद भ्रमण से खर्च पर नियंत्रण रहता है। इस दौरान रिलायंस इन्फोस्टेक्चर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट स्मार्ट ग्रिड अजय राजपानी, राजकॉम इफो रॉबिंसेज लिमिटेड के डायरेक्टर (टी) उदय शंकर, नेटएप इंडिया के सिस्टम इंजीनियर कृष्ण परमार ने भी विचार रखे।

**सेकंड रेशन:** डिजिटल पोपल टुगेदर- स्ट्राइकिंग फॉर गोर एक्टिव, सेफ, रेजिलियंट एंड एंगेज्ड कम्युनिटीज

कॉन्टैक लोकायुक्त एवं बैंगलूरु के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय सहाय ने कहा कि स्मार्ट सिविलिटी सिस्टम के लिए शहरों में कैमरे नहीं होने चाहिए, जहां इनकी आवश्यकता हो और इसमें कवरेज एरिया का ध्यान भी रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऑरिएण्टल सेंटर्स और प्रशिक्षित कार्टेबल्स के जरिए तकनीक का बेहतर इस्तेमाल भी होना चाहिए। सूरत नगर निगम के उपायुक्त एवं स्मार्ट सिटी सूरत के सीईओ नागराज एम. ने कहा कि भारत में स्मार्ट सिटीज के विकास में एक बड़ी चुनौती राज्य व केंद्र के मध्य संवाद और समन्वय की कमी है।

राजस्थान में लगेंगे 2.50 लाख स्मार्ट मीटर

स्मार्ट एंड डिजीटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो में हुआ मंथन

शहरों में कैमरे वहीं होने चाहिए, जहां इनकी आवश्यकता हो

नया एक्सपोज़िचर  
भारत को स्मार्ट सिटी अखाद्य में  
अन्य देशों की नकल नहीं होनी चाहिए।  
इसमें भारत का अनूठा व्यक्तित्व और  
स्टाइल दिखाना चाहिए। यह बात पनजी  
म्योबल एग्जिडि एक्जिक्यूसिव के सीईओ  
एन टुवर्क के स्मार्ट सिटी कंसल्टेंट, एन.जी.  
धीमरा ने कही।  
ये मुख्यार को होटल जयपुर में  
स्मार्ट एंड डिजीटल राजस्थान समिट  
एंड एक्सपो 2018 के समापन सत्र में  
संयोजक कर रहे थे। भारत को स्मार्ट  
सिटीय के विकास में योगदान देने वाली  
सबसे बड़ी सेक्टर इसमें रहने वाले योग्य  
है। स्मार्ट सिटीय में पहले दिने से ही पैसा  
जेनरेट करना चाहिए। विभिन्न सेवाओं  
को उपस्थित कराने के बदले बड़ी  
उत्सुकता से छोटा या मुक्त निगम जहां  
तो सरकारक वित्तीय परिणाम प्राप्त हो  
सकते हैं। इस अवसर पर आर्किटेक्चर  
को पहिली एंड एक्जिक्यूसिव कंपेटो के  
चेयरमैन, पी. सुरेश ने कहा कि स्मार्ट  
सिटीय को स्मार्ट ग्रोन सिटीय में बदलने



को जरूरत है। इसमें इन शहरों में पानी,  
बिजली को खपत कम होनी, कचरे का  
बेहतर निस्कारण योग्य और इनमें रहने  
वाली को अच्छी अवास सुविधा मिल  
सकेगी। इस अवसर पर ज.मानको

पहला सत्र  
स्मार्ट सिटी की सफलता की कुंजी है  
तकनीक, नवाचार और सहयोग

सेक्टर फॉर रिसर्च इन अर्बन इंफ्रस्ट्रक्चर ऑफ सोशल एंड  
इकोनॉमिक वेज की प्रोफेसर, डॉ. कला सीकरमन श्रीधर ने कहा कि इ-  
कॉमर्स और इंटरनेट जैसे नए आर्थिक उद्योग विकसल रहे हैं। इ-कॉमर्स में अमेज़न,  
लंबोर्न आदि के जरिए ऑन लाइन शॉपिंग ने शॉपिंग के परम्परागत  
तरीके बदल दिए हैं। भारत में भारत को टॉप 31 प्रतियोग है, जबकि  
अमेरिका में यह नंबर 17 प्रतियोग है। ऑनलाइन कारुस प्रोडिक्ट स्मार्ट सिटी,  
दिल्लीयस इन्फ्रास्ट्रक्चर अकादम राजपाली ने कहा कि वर्तमान में गुरुशालन  
समुदाय बनाने की आवश्यकता है जो उपभोक्ताओं को स्मार्ट सिटीय में डीजी  
सुविधाएं दे। राजस्थान में 2.50 लाख स्मार्ट मीटर लगाया जाना  
प्रस्तावित है। इन्फोरेटर (टी) राजकोम्य इन्फो रजिस्ट्रार लिमिटेड के अध्यक्ष  
शंकर ने कहा कि ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर जो अच्छे नेटवर्क और बेहतर  
कनेक्टिविटी में सक्षम हो, गार्बी तक पहुंचना चाहिए। राजस्थान सरकार  
के नवाचार जैसे इ-गिज परस, इलेक्ट्रॉनिक गैस रिक्वर्ड (एडिपआर),  
रजिस्ट्रार के लिए ड्रॉन्स और मोंगटोल पैस आदि ये लोगों को स्मार्ट  
और डिजीटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। मोटाप हॉबिआ के सिस्टम  
इंजीनियर कृष्ण परमार ने 'डिजीटलिंग द हेल्थ सेज द वर्ल्ड रिड ड्राटा'  
थिमा पर प्रजेंटेशन दिया। इस प्रजेंटेशन में माइक्रो के लिए ड्राटा के  
एडे विकल्प उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

दूसरा सत्र  
ब्रिगिंग पीपल टुगेदर- स्ट्राइविंग  
फॉर मोर एक्टिव, सेफ, रेजिलियंट  
एंड एंगेज्ड कम्युनिटीज

कनेक्ट लोकयुक्त एवं बंगलौर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक  
संजय सुख ने कहा कि स्मार्ट सिटीयोंमें सिस्टम के लिए शहरों में  
कैमरे नहीं होने चाहिए, जहां इनकी आवश्यकता हो और इसमें कनेक्ट  
एरिया का ध्यान भी रखा जाय। इसके अतिरिक्त ऑनरेसलुव सेक्टर  
और प्रतियोग कंसल्टंट के जरिए राकली का बेहतर इन्फोमेशन भी  
शेरा चाहिए। इस नजराने से नॉनप्रिडिग और प्रगति का अन्वयन अभी  
भी बचा मुदा बना हुआ है। भिखीत ऑडिओ और ट्रेकिंग मेट्रोपल अभी  
सिस्टम के परीक्षण से इस मुदे का समाधान किया जा सकता है।  
सुरत कगर निगम के उपयुक्त एवं स्मार्ट सिटी सुरत के सीईओ  
कनारजल एम. ने कहा कि भारत में स्मार्ट सिटीय के विकास में एक  
बड़ी चुनौती राज्य व केन्द्र के म्या संवाद और उत्सुकता की कमी है।  
राजस्थान सोलर एसीसिशन के म्हासचिव सुनील बंसल ने कहा कि  
पीन एनर्जी सी लागत ज्यादा होने के बावजूद सरकार को इन पर  
ध्यान देना होगा ताकि शहरों को लोगों के रहने लयबद्ध बनाया जाय  
और आर्थिक सुख रहे। इंडीयास्ट्रिज, सेक्टर लवटूर, मॉडर्न लाइट्स  
के लिए सरकार को नीतिगत बलाबी चाहिए। वाइब्रेट सोलर के एमडी  
अर.एस. राजगुप्टिन ने भी इस अवसर पर अपने विचार राखन किए।

# स्मार्ट सिटीज को स्मार्ट ग्रीन सिटी में बदलने की जरूरत

चर्चा

■ स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो 2018 का समापन

पंजाब कैसरी/जयपुर

आज देश में स्मार्ट सिटीज बनाने पर जो काम चल रहा है, उसमें ग्रीन सिटीज बनाने पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इससे न केवल इन शहरों में पानी, बिजली की खपत कम होगी, कचरे का बेहतर निस्तारण होगा। ये बात गुरुवार को स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो 2018 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए आईजीबीसी की पॉलिसी एंड एडवोकेसी कमेटी के चेयरमैन वी. सूरेश ने कही। वहीं दूसरी तरफ दुर्जित के स्मार्ट सिटी कंसल्टेंट एन.जी. थॉमस ने कहा कि भारत को स्मार्ट



स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो 2018 के समापन सत्र में मंचासीन अतिथि।

सिटी अवधारणा में अन्य देशों की नकल नहीं होनी चाहिए। इसमें भारत का अनूठा व्यक्तित्व और स्टाइल दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को स्मार्ट सिटीज के विकास में योगदान देने वाली सबसे बड़ी ऐसेट इसमें रहने वाले लोग हैं।

**लगेगे स्मार्ट मीटर:** एक्सपो को संबोधित करते हुए रिलायंस इन्फोटेकनॉलॉजी के सीनियर वाइस प्रेसीडेंट अजय राजपानी ने कहा कि वर्तमान में खुशहाल समुदाय बनाने की आवश्यकता है, जो उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर्स जैसी सुविधाएं दे।

राजस्थान में 2.50 लाख स्मार्ट मीटर लगाया जाना प्रस्तावित है। इससे उपभोक्ताओं को स्वयं की बिजली की खपत पर नजर रखने में सहायता मिलेगी और वे बिजली की खपत पर नियंत्रण कर अपनी लागत कम कर सकेंगे।



## ‘भारत की स्मार्ट सिटी अवधारणा में दिखना चाहिए इसका अनूठा व्यक्तित्व और स्टाइल : एनजी थॉमस

स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो-2018 का समापन

**जयपुर (कासं)।** भारत की स्मार्ट सिटी अवधारणा में अन्य देशों की नकल नहीं होनी चाहिए। इसमें भारत का अनूठा व्यक्तित्व और स्टाइल दिखना चाहिए। यह बात एनजी ग्लोबल एफजेड एलएएलसी के सीईओ एवं दुबई के स्मार्ट सिटी कंसल्टेंट, एन.जी. थॉमस ने कही। वे गुरुवार को होटल जयपुर मेरियट में स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो 2018 के समापन सत्र में सम्बोधित कर रहे थे। भारत की स्मार्ट सिटीज के विकास में योगदान देने वाली सबसे बड़ी एसेट में रहने वाले लोग हैं। स्मार्ट सिटीज में पहले दिन से ही पैसा

जेनेरेट करना चाहिए। विभिन्न सेवाओं को उपलब्ध करने के बंदले बड़ी जनसंख्या से छोटा सा शुल्क लिया जाए तो सकारात्मक वित्तीय परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस अवसर पर आईजीबीसी की पॉलिसी एंड एडवोकेसी कमेटी के चेयरमैन, वी. सुरेश ने कहा कि स्मार्ट सिटीज को स्मार्ट ग्रीन सिटीज में बदलने की जरूरत है। इससे इन शहरों में पानी, बिजली की खपत कम होगी, कचरे का बेहतर निस्तारण होगा और इनमें रहने वालों को अच्छी आवास सुविधा मिल सकेगी। इस अवसर पर जे. मोहनको. कंस्ट्रक्शन्स के मैनेजिंग पार्टनर, जैमिनी उबेरॉय ने कहा कि कई

कम्पनियां भी स्मार्ट, डिजिटल और ग्रीन होने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एआईसीसी की रीजनल वाइस प्रेसीडेंट, अरूणा सेठी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। पहले सत्र के दौरान सेंटर फॉर रिसर्च इन अर्बन अफेयर्स इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज की प्रोफेसर, डॉ. कला सीतारामन श्रीधर ने कहा कि ई-कॉमर्स और इंटरनेट जैसे नए आर्थिक उद्योग पनपना इस का बात का संकेत है कि प्राचीन आर्थिक उद्योग विफल रहे हैं।

कर्नाटक लोकायुक्त एवं बंगलौर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय सहाय ने कहा कि स्मार्ट सिक्वोरिटी

सिस्टम के लिए शहरों में कैमरे वहीं होने चाहिए जहां इनकी आवश्यकता हो और इसमें कवरेज एरिया का ध्यान भी रखना चाहिए। राजस्थान सोलर एसोसिएशन के महासचिव, सुनील बंसल ने कहा कि ग्रीन एनर्जी की लागत ज्यादा होने के बावजूद सरकार को इस पर ध्यान देना होगा ताकि शहरों को लोगों के रहने लायक बनाया जाए और नागरिक खुश रहें।

स्ट्रीटलाइट्स, सेंसर लाइट्स, गार्डन लाइट्स के लिए सरकार को नीतियां बनानी चाहिए। वाइब्रेंट सोलर के एमडी आर.एस. राजपुरोहित ने, भी इस अवसर पर अपने विचार साझा किये।

## भारत की स्मार्ट सिटी अवधारणा में दिखना चाहिए अनूठा व्यक्तित्व और स्टाइल : एन.जी. थॉमस



■ जलतेदीप कासं, जयपुर

भारत की स्मार्ट सिटी अवधारणा में अन्य देशों की नकल नहीं होनी चाहिए। इसमें भारत का अनूठा व्यक्तित्व और स्टाइल दिखनी चाहिए। यह बात एनजी ग्लोबल एफजेड एलएएलसी के सीईओ एवं दुबई के स्मार्ट सिटी कंसल्टेंट एन.जी. थॉमस ने कही। वे गुरुवार को होटल जयपुर मेरियट में स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो-2018 के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि

सकारात्मक वित्तीय परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

इस अवसर पर आईजीवीसी की पॉलिसी एंड एडवोकेसी कमेटी के चेयरमैन वी. सुरेश ने कहा कि स्मार्ट सिटीज को स्मार्ट ग्रीन सिटीज में बदलने की जरूरत है। इससे इन शहरों में पानी-बिजली की खपत कम होगी, कचरे का बेहतर निस्तारण होगा और इनमें रहने वालों को अच्छी आवास सुविधा मिल सकेगी। स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए वित्तीय संसाधन आवश्यक हैं। स्मार्ट सिटीज के लिए बांड्स, ग्रांट्स, टैक्स कलेक्शन आदि के जरिए

भारत की स्मार्ट सिटीज के विकास में योगदान देने वाली सबसे बड़ी संपत्ति इसमें रहने वाले लोग हैं। स्मार्ट सिटीज में पहले दिन से ही पैसा जेनरेट करना चाहिए। विभिन्न सेवाओं को उपलब्ध कराने के बदले बड़ी जनसंख्या से छोटा सा शुल्क लिया जाए तो

वित्तीय संसाधन जुटाने में निजी और सरकारी क्षेत्र के मध्य उचित संतुलन आवश्यक है।

इस अवसर पर जे.मोहनको कंस्ट्रक्शंस के मैनेजिंग पार्टनर जैमिनी उबेरॉय ने कहा कि कई कंपनियां भी स्मार्ट, डिजिटल और ग्रीन होने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एआईसीसी की रीजनल वाइस प्रेसिडेंट अरुणा सेठी ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

पहला सत्र - स्मार्ट सिटी की सफलता की कुंजी है तकनीक, नवाचार और सहयोग

सेंटर फॉर रिसर्च इन अर्बन अफेयर्स इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज की प्रोफेसर डॉ. कला सीतारमण श्रीधर ने कहा कि ई-कॉमर्स और इंटरनेट जैसे नए आर्थिक उद्योग पनपना इस का बात के संकेत हैं कि प्राचीन आर्थिक उद्योग विफल रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 'वर्क फ्रॉम होम' जैसी अवधारणाओं से ट्रेफिक और प्रदूषण कम होता है। इसी तरह ई-कॉमर्स में अमेजन, जबॉग आदि के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग ने शॉपिंग के परंपरागत तरीके बदल दिए हैं। भारत में बचत की दर 31 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका में यह सिर्फ 17 प्रतिशत है। यह इसलिए है कि भारत में आज भी लोग भुगतान के लिए नकदी का इस्तेमाल करते हैं। नकद भुगतान से खर्च पर नियंत्रण रहता है।



स्मार्ट एंड डिजीटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो 2018 का हुआ समापन

# स्मार्ट सिटी अवधारणा में दिखना चाहिए भारतीय स्टाइल: थॉमस

भारत की स्मार्ट सिटी अवधारणा में अन्य देशों की नकल नहीं होनी चाहिए। इसमें भारत का अनूठा व्यक्तित्व और स्टाइल दिखना चाहिए। यह बात एनजी ग्लोबल एफजेड एलएएलसी के सीईओ एवं दुबई के स्मार्ट सिटी कंसल्टेंट, एन.जी. थॉमस ने कही।

कंचन केसरी

जयपुर/कासं। एनजी ग्लोबल एफजेड एलएएलसी के सीईओ एवं दुबई के स्मार्ट सिटी कंसल्टेंट, एन.जी. थॉमस ने स्मार्ट एंड डिजीटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो 2018 के समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए कहा कि भारत की स्मार्ट सिटीज के विकास में योगदान देने वाली सबसे बड़ी ऐसेट इसमें रहने वाले लोग हैं। स्मार्ट सिटीज में पहले दिन से ही पैसा जेनरेट करना चाहिए। विभिन्न सेवाओं को उपलब्ध कराने के बदले बड़ी जनसंख्या से छोटा सा शुल्क लिया जाए तो सकारात्मक वित्तीय परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।



स्मार्ट सिटीज को स्मार्ट ग्रीन सिटीज में बदलने की जरूरत

आईजीबीसी की पॉलिसी एंड एडवोकेसी कमेटी के चेयरमैन, वी. सुरेश ने कहा कि स्मार्ट सिटीज को स्मार्ट ग्रीन सिटीज में बदलने की जरूरत है। इससे इन शहरों में पानी, बिजली की खपत कम होगी, कचरे का बेहतर निस्तारण होगा और इनमें रहने वालों को अच्छी आवास सुविधा मिल सकेगी। स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए वित्तीय संसाधन आवश्यक हैं। स्मार्ट सिटीज के लिए बैंड्स, ग्रांट्स, टैक्स कलेक्शन, आदि के जरिए वित्तीय संसाधन जुटाने में निजी और सरकारी क्षेत्र के मध्य उचित संतुलन आवश्यक है। इस अवसर पर जे. मोहन को कंसल्टिंग के मैनेजिंग पार्टनर, जैमिनी उबेरॉय ने कहा कि कई कम्पनियां भी स्मार्ट, डिजीटल और ग्रीन होने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एआईसीसी की रीजनल वाइस प्रेसीडेंट, अरुणा सेठी ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

भारत में बचत की दर 31 प्रतिशत

सेंटर फॉर रिसर्च इन अर्बन आफेयर्स इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज की प्रोफेसर, डॉ. कला सीतारमन श्रीधर ने कहा कि ई-कॉमर्स और इंटरनेट जैसे नए आर्थिक उद्योग पनपना इस बात का संकेत है कि प्राचीन आर्थिक उद्योग विफल रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि वर्क फ्रॉम होम जैसी अवधारणाओं से ट्रेफिक और प्रदूषण कम होता है। इसी तरह ई-कॉमर्स में अमेजन, जर्बॉग आदि के जरिए ऑन लाइन शॉपिंग ने शॉपिंग के परम्परागत तरीके बदल दिए हैं। भारत में बचत की दर 31 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका में यह सिर्फ 17 प्रतिशत है। यह इसलिए है कि भारत में आज भी लोग भुगतान के लिए नकदी का इस्तेमाल करते हैं। नकद भुगतान से खर्च पर नियंत्रण रहता है।

# “भारत की स्मार्ट सिटी अवधारणा में दिखना चाहिए इसका अनूठा व्यक्तित्व और स्टाइल”



**जयपुर।** भारत की स्मार्ट सिटी अवधारणा में अन्य देशों की नकल नहीं होनी चाहिए। इसमें भारत का अनूठा व्यक्तित्व और स्टाइल दिखना चाहिए। यह बात एनजी ग्लोबल एफबेड एंडएएलसी के सीईओ एवं दुबई के स्मार्ट सिटी कंसल्टेंट, एन.जी. थॉमस ने कहे। वे आज होटल जयपुर मेरिडियन में स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो 2018 के समापन सत्र में सम्बोधित कर रहे थे। भारत की स्मार्ट सिटीज के विकास में योगदान देने वाली सबसे बड़ी एसेट इयमें रहने वाले लोग हैं। स्मार्ट सिटीज में पहले दिन से ही पैसा जेनेट करना चाहिए। विभिन्न सेवाओं को उपलब्ध करने के बदले बड़ी जनसंख्या से छोटा सा

शुल्क लिया जाए तो सकारात्मक वित्तीय परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस अवसर पर आईजीबीसी की पॉलिस्मी एंड एडवोकेसी कमेटी के चेयरमैन, वी. सुरेश ने कहा कि स्मार्ट सिटीज को स्मार्ट ग्रीन सिटीज में बदलने की जरूरत है। इससे इन शहरों में पानी, बिजली की खपत कम होगी, कचरे का बेहतर निस्तारण होगा और इनमें रहने वालों को अच्छी आवास सुविधा मिल सकेगी। स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए वित्तीय संसाधन आवश्यक हैं। स्मार्ट सिटीज के लिए बाइपास, ग्रांट्स, टैक्स कालेजेशन, आदि के जरिए वित्तीय संसाधन जुटाने में निजी और सरकारी क्षेत्र के, मध्य उचित संतुलन आवश्यक है। इस अवसर पर जे. मोहन को

कॉन्ट्रक्चर के मैनेजिंग पार्टनर, जैमिनी उद्योग ने कहा कि कई कंपनियों भी स्मार्ट, डिजिटल और ग्रीन होने के लिए प्रयत्न कर रही हैं। एआईसीसी की राजनल वाइस प्रेसिडेंट, सुशी अरुणा सेठी ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

**पहला सत्र- स्मार्ट सिटी का सफलता की कुंजी है तकनीक, नवाचार और सहयोग:** सेंटर फॉर रिसर्च इन अर्बन अफेयर्स इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज की प्रोफेसर, डॉ. कला सोतारमन शोध ने कहा कि ई-कॉमर्स और इंटरनेट जैसे नए आर्थिक उद्योग पनपना इस का सात का संकेत हैं कि प्राचीन आर्थिक उद्योग विफल रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि 'बर्क फ्रॉम होम' जैसी अवधारणाओं

से ट्रेडिक और प्रदूषण कम होता है। इसी तरह ई-कॉमर्स में अमेजन, जॉब्स आदि के जरिए ऑन लाइन शॉपिंग ने शॉपिंग के परम्परागत तरीके बदल दिये हैं। भारत में बचत की दर 31 प्रतिशत है, जबकि अमेरिका में यह सिर्फ 17 प्रतिशत है। यह इसलिए है कि भारत में आज भी लोग भुगतान के लिए नकदी का इस्तेमाल करते हैं। नकद भुगतान से खर्च पर नियंत्रण रहता है।

राजस्थान वाइस प्रेसिडेंट स्मार्ट ग्रिड, रिलायंस इन्फ्रस्ट्रक्चर, अजय राजपानी ने कहा कि वर्तमान में खुशहाल समुदाय बनाने की आवश्यकता है जो उपभोक्ताओं को स्मार्ट मोड में जैसी सुविधाएं दे। राजस्थान में 2.50 लाख स्मार्ट मीटर लगाया जाना प्रस्तावित है। इससे उपभोक्ताओं को स्वयं की बिजली की खपत पर नजर रखने में सहायता मिलेगी और वे बिजली की खपत पर नियंत्रण कर अपनी लागत कम कर सकेंगे।

**डायरेक्टर (टी) राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड के उदय शंकर ने कहा कि ऐसा इन्फ्रान्स्ट्रक्चर जो अच्छे नेटवर्क और बेहतर कनेक्टिविटी में**

सक्षम हो, गांवों तक पहुंचना चाहिए। छोटे शुल्क के बदले नागरिकों को सिंगल प्लेटफॉर्म पर सरकारी सुविधाएं मिल जाएं तो वह उनके लिए काफी लाभदायक है। राजस्थान सरकार के नवाचार जैसे ई-मिथ प्लस, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकार्ड (ईएचआर), सर्विलंस के लिए ड्रोनस और मोबाइल कैस आदि से लोगों को स्मार्ट और डिजिटल सेवाएं आताओं से मिल सकेंगी।

नेटएप इंडिया के सिस्टम इंजीनियर, कृष्ण परमार ने 'इनेवेटिंग टू हैल्प बेंच द वर्ल्ड विद डेटा' विषय पर प्रजेंटेशन दिया। इस प्रजेंटेशन में नागरिकों के लिए डेटा के ऐसे विकल्प उपलब्ध करने पर जोर दिया गया जो सुरक्षित, कुशल और प्रविष में भी उपयोगी हो।

**द्वितीय पैनल सत्र-ड्रिगिंग पीपल टुरादर-स्ट्राइविंग फॉर मोर एक्टिव, सेफ रोजिलिबंट एंड एंगेज्ड कम्युनिटीज:** कर्नाटक लोकयुव एवं वेश्ठीर के आतिथिक पुलिस महानिदेशक, संबन्ध सहाय ने कहा कि स्मार्ट सिटीयों में सिस्टम के लिए शहरों में कैमरे नहीं होने चाहिए, जहां इनकी आवश्यकता हो और इसमें कवरेज एरिया का ध्यान भी

रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त ऑपरेशनल सेंटर्स और प्रेषित कॉन्स्ट्रक्श के जरिए तकनीक का बेहतर इस्तेमाल भी होना चाहिए। इस मामले में मोनिटरिंग और प्राति का अकलन अभी भी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। नियमित ऑडिट और ट्रेडिक मैनेजमेंट सिस्टम के परिधर्णों से इस मुद्दे का समाधान किया जा सकता है।

सूतल नगर निगम के उपायुक्त एवं स्मार्ट सिटी सुरत के सीईओ, नगराजन एम. ने कहा कि भारत में स्मार्ट सिटीज के विकास में एक बड़ी चुनौती राज्य व केंद्र के मध्य संबन्ध और समन्वय की कमी है।

राजस्थान सोलर एरोसिपेरशन के महासचिव, सुनील बंसल ने कहा कि ग्रीन पननी की लागत ज्यादा होने के बावजूद सरकार को इस पर ध्यान देना होगा ताकि शहरों को लोगों के रहने लायक बनाया जाए और नागरिक खुश रहें।

स्ट्रीटलाइट्स, सेंसर लाइट्स, गाडन लाइट्स के लिए सरकार को नीतियां बनानी चाहिए। चाइंड्रेड सोलर के एमडी आर.एस. राजपुरोहित ने भी उस अवसर पर अपने विचार साझा किये।



भारत की स्मार्ट सिटी अवधारणा में दिखना चाहिए  
अनूठा व्यक्तित्व और स्टाइल : एन.जी. थॉमस



जयपुर। भारत की स्मार्ट सिटी अवधारणा में अन्य देशों की नकल नहीं होनी चाहिए। इसमें भारत का अनूठा व्यक्तित्व और स्टाइल दिखनी चाहिए। यह बात एनजी ग्लोबल एफजेड एलएएलसी के सीईओ एवं दुबई के स्मार्ट सिटी कंसल्टेंट एन.जी. थॉमस ने कही। वे गुरुवार को होटल जयपुर मेरियट में स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिट एंड एक्सपो-2018 के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की स्मार्ट सिटीज के विकास में योगदान देने वाली सबसे बड़ी संपत्ति इसमें रहने वाले लोग हैं। स्मार्ट सिटीज में पहले दिन से ही पैसा जेनरेट करना चाहिए। विभिन्न सेवाओं को उपलब्ध कराने के बदले बड़ी जनसंख्या से छोटा सा शुल्क लिया जाए तो सकारात्मक वित्तीय परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस अवसर पर

आईजीबीसी की पॉलिसी एंड एडवोकेसी कमेटी के चेयरमैन वी. सुरेश ने कहा कि स्मार्ट सिटीज को स्मार्ट ग्रीन सिटीज में बदलने की जरूरत है। इससे इन शहरों में पानी-बिजली की खपत कम होगी, कचरे का बेहतर निस्तारण होगा और इनमें रहने वालों को अच्छी आवास सुविधा मिल सकेगी। स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए वित्तीय संसाधन आवश्यक हैं। स्मार्ट सिटीज के लिए बांड्स, ग्रांट्स, टैक्स कलेक्शन आदि के जरिए वित्तीय संसाधन जुटाने में निजी और सरकारी क्षेत्र के मध्य उचित संतुलन आवश्यक है। इस अवसर पर जे.मोहनको कंसल्टिंग के मैनेजिंग पार्टनर जैमिनी उबेरॉय ने कहा कि कई कंपनियां भी स्मार्ट, डिजिटल और ग्रीन होने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एआईसीसी की रीजनल चाइस प्रेसीडेंट अरुणा सेठी ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

# बुलेटिन टुडे

गुरुवार  
15.03.2018

## हमारी भौगोलिक स्थितियां अन्य देशों से भिन्न : लाहोटी

**जयपुर।** जयपुर नगर निगम के महापौर अशोक लाहोटी ने कहा कि स्मार्ट सोल्यूशन्स को लागू करने से पूर्व हमें सीवरेज, प्रदूषण नियंत्रण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट, परिवहन के वैकल्पिक साधन और अन्य मूल घटकों के विकास पर ध्यान देना होगा। स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिट और एक्सपो 2018 को संबोधित करते उन्होंने कहा कि विदेशों की तरह स्मार्ट सिटी डवलपमेंट की अवधारणा को यहां ज्यों का त्यों लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे देश की भौगोलिक, डेमोग्राफिक एवं आर्थिक स्थितियां अन्य देशों से भिन्न हैं।

## राजस्थान स्टेटमेन्ट

जयपुर गुरुवार, 15 मार्च, 2018

# स्मार्ट सिटी से पहले मूलभूत सुविधाओं का विकास होना जरूरी-मेयर

(राजस्थान स्टेटमेन्ट) जयपुर। स्मार्ट सॉल्यूशन्स को लागू करने से पूर्व हमें सीवरेज, प्रदूषण नियंत्रण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट, परिवहन के वैकल्पिक साधन और अन्य मूल घटकों के विकास पर ध्यान देना होगा।

यह बात जयपुर के मेयर, अशोक लाहोटी ने कही है। वे आज जयपुर मैरियट में 'स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिट और एक्सपो 2018' के उद्घाटन सत्र में सम्बोधित कर रहे थे। दो दिवसीय

इस समिट का आयोजन इंडो-अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (आईएसीसी) द्वारा राजस्थान सरकार एवं 'द गिल्ड' के सहयोग से किया जा रहा है। इस आयोजन को राजस्थान सरकार के शहरी विकास एवं आवासन (यूडीएच) विभाग का भी सहयोग प्राप्त है। इस अवसर पर आईएसीसी के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, डॉ. ललित भसीन ने स्वागत भाषण में बताया कि किसी भी शहर के विकास के स्तर, बदलाव की

इच्छा, नागरिकों की महत्वाकांक्षा से उस शहर की स्मार्ट सिटी की परिभाषा तय होती है। स्मार्ट सिटी में ऐसे स्थान आवश्यक हैं जहां लोग पैदल चल सकें, खुली जगह हो, परिवहन के अच्छे विकल्प उपलब्ध हों और नागरिकों के अनुकूल एवं किफायती प्रशासन हो। इस अवसर पर अमेरिका के अनुभव साझा करते हुए यूएस कमर्शियल सर्विसेज की काउंसलर, ऐलीन क्रोव नेंडी ने कहा कि भारत के स्मार्ट बनने की असीम सम्भावनाएं हैं।



## सांध्य ज्योति दर्पण

जयपुर, गुरुवार, 15 मार्च, 2018



### स्मार्ट सिटी के लिए जनता को दें बेहतर सुविधाएं : लाहोटी

सांध्य ज्योति संवाददाता  
जयपुर, 15 मार्च। किसी भी शहर को स्मार्ट सिटी बनाने उसमें स्मार्ट सॉल्यूशन्स को लागू करने से पहले वहां की जनता को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना सबसे जरूरी है। जब तक उस शहर में सीवरेज, पानी-बिजली, प्रदूषण नियंत्रण, इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट, परिवहन के वैकल्पिक साधन नहीं होंगे, तब तक स्मार्ट सॉल्यूशन्स को लागू करने का कोई औचित्य नहीं है। ये बात बुधवार को मेयर असोक लाहोटी ने एक होटल में आयोजित स्मार्ट एंड डिजिटल राजस्थान समिट और एक्सपो 2018 के उद्घाटन सत्र को

सम्बोधित करते हुए कही।

दो दिवसीय इस समिट का आयोजन इंडो-अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स (आईएसीसी) द्वारा राजस्थान सरकार और द गिल्ड के सहयोग से किया जा रहा है। इस आयोजन को राजस्थान सरकार के शहरी विकास एवं आवासन (यूडीएच) विभाग का भी सहयोग प्राप्त है। इस अवसर पर आईएसीसी के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेसीडेंट, डॉ. ललित भसीन ने बताया कि किसी भी शहर के विकास के स्तर, बदलाव की इच्छा, नागरिकों की महत्वाकांक्षा से उस शहर की स्मार्ट सिटी की परिभाषा तय होती है। स्मार्ट सिटी में ऐसे स्थान आवश्यक

हैं जहां लोग पैदल चल सकें, खुली जगह हो, परिवहन के अच्छे विकल्प उपलब्ध हों और नागरिकों के अनुकूल एवं किफायती प्रशासन हो। इस मौके पर अमेरिका के अनुभव साझा करते हुए यूएस कमर्शियल सर्विसेज की कमर्शियल काउंसलर, ऐलीन क्रोव नेंडी ने कहा कि भारत के स्मार्ट देश बनने की असीम सम्भावनाएं हैं। यहां शहरीकरण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में स्वच्छ जल, बिजली और परिवहन बेहद जरूरी हैं। अनेक अमेरिकी कम्पनियां स्मार्ट सिटी डवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए स्मार्ट और नए तरह के सॉल्यूशन्स उपलब्ध कराती हैं।